Appraisal Report of World Bank on Upper Krishna Project

5270. SHRI RAJSHEKHAR KOLUR: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether the Government of India has received the Appraisal Report of the World Bank on Upper Krishna Project in Karnataka ; and

(b) if so, details thereof ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) Preliminary Appraisal Report of the World Bank was received in the month of February, 1978, on the basis of which negotiations were concluded in March, 1978. Final Report is however, awaited.

(b) According to the negotiations conducted in March, 1978, the Bank has estimated the project cost at S 252 million and IDA would provide a credit of US S 126 million. The first phase of the project for which the assistance is provided, comprises completion of it:

(i) the Narayanpur Dam to full height and Almatti Dam to Stage I height,

(ii) Narayanpur Left Bank Canal and Shahapur Branch,

(iii) Irrigation distribution system to serve an area of 127,000 ha. field channels to individual farms to cover an area of 80,000 ha.,

(iv) land shaping and field drainage channels to cover 25,000 ha., ond

(v) It also includes proposals for construction of field channels and land-shaping in Malaprabha and Ghataprabha irrigation project commands to serve an area of 26,000 and 5,000 ha. respectively. This phase of the project is expected to be completed in a period of 5 years (from 1978-79 to 1982-83).

ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का खोला जाना

5271. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में कमजोर वर्गों एवं हरिजनों में व्याप्त निरक्षरता को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नये स्कूल खोलने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार, देश में सर्वव्यापी साक्षरता की प्राप्ति सरकार की घोषित नीति है। 6—14 वर्ष आयु-वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाना तथा राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 15—35 आयु-वर्ग के निरक्षर प्रौढ़ों को साक्षर बनाना इस नीति के दो घटक हैं । दाखिल न होने वाले बच्चों में, जो हर प्रयास के बावजूद भी स्कूल नहीं जा पाते हैं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों जैसे समाज के कमजोर वर्गों के बच्चे शामिल हैं तथा प्रौढ़ निरक्षरों का एक बड़ा भाग भी समाज के इन वर्गों से ही संबंधित है ।

अगले 5—7 वर्षों की अवधि में अनुमानित 4.52 करोड़ अतिरिक्त दाखिल न होने वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा